CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो डीएपी उर्वरक लॉन्च किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफको के तरल नैनो डाई-अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) का शुभारंभ किया।

शाह ने कहा कि आज दुनिया में पहला नैनो डीएपी (लिक्विड) लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि यह क्रांतिकारी कदम न केवल भारतीय कृषि को खाद्यान्न उत्पादन में आगे ले जाएगा बल्कि यह भारत को उर्वरक उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाएगा।

इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा, "इफको के तरल डीएपी नैनो का शुभारंभ भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है।"

नैनो डीएपी का निर्माण सहकारी प्रमुख इफको द्वारा किया जाता है। हाल ही में, केंद्र ने उर्वरक नियंत्रण आदेश में नैनो डीएपी को अधिसूचित किया था, जो देश में उर्वरकों की बिक्री, मूल्य निर्धारण और वितरण को नियंत्रित करता है।

मई 2021 में इफको ने नैनो यूरिया लॉन्च किया।

पंचायतों में डेयरी सहकारी समितियों को मदद बढ़ाएं: अमित शाह एनडीडीबी से

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से वंचित पंचायतों और गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना में मदद करने और देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने को कहा।

डेयरी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंत्री ने यहां एनडीडीबी के बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की।

उन्होंने बहु-वस्तु सहकारी समितियों, निर्यात के लिए सामान्य ब्रांडों, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के बेहतर क्षमता उपयोग सहित अन्य की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शाह ने डेयरी बोर्ड से कहा कि डेयरी के लिए संभावित गैर-पंचायतों/गांवों में व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाकर सहकारी डेयरी को और मजबूत किया जाए।

महाराष्ट्र के स्कूलों में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा

कृषि को जल्द ही एक विषय के रूप में पेश किया जाएगा और महाराष्ट्र शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र कृषि, शिक्षा और अनुसंधान परिषद (MCAER) और महाराष्ट्र राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (MSCERT) को पाठ्यक्रम विकसित करने में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है।

स्कूलों में इस विषय को पढ़ाने का निर्णय लेने के लगभग दो साल बाद राज्य प्रशासन ने कृषि के लिए एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम योजना जारी की है। राज्य के कृषि और शिक्षा विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालय के प्रशिक्षकों के एक समूह द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सभी कक्षाओं में कृषि संबंधी विषयों को पढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम में कृषि सहित कई व्यावसायिक विषयों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने डेयरी उद्योग में महिलाओं की भूमिका पर दिया जोर, अधिक समर्थन का आह्वान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के डेयरी उद्योग प्रबंधन में महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में क्षेत्र के योगदान पर जोर दिया। मुर्मू ने करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-एनडीआरआई) के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए महिलाओं के लिए शैक्षिक, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आसान ऋण पहुंच और बाजार में प्रवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग भारत की जीडीपी में लगभग 5% का योगदान देता है और लगभग 80 मिलियन परिवारों का समर्थन करता है, जो देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, "एनडीआरआई जैसे संस्थानों को देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।"

भारत में गायों और पशुओं के सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को स्वीकार करते हुए, मुर्मू ने उच्च दूध देने वाले मवेशियों के लिए क्लोनिंग तकनीक के एनडीआरआई के विकास की प्रशंसा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तकनीक दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती है और किसानों की आय में सुधार कर सकती है।

दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति के बावजूद, दुग्ध उत्पाद की बढ़ती मांग, चारे की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और पशुधन रोगों सहित चुनौतियां बनी हुई हैं। मुर्मू ने पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह करते हुए स्थायी दूध उत्पादन और डेयरी खेती के महत्व को रेखांकित किया, जो पशु कल्याण पर विचार करती हैं।

राष्ट्रपति ने डेयरी फार्मों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के एनडीआरआई के प्रयासों की सराहना की और बायोगैस उत्पादन जैसे स्वच्छ ऊर्जा पर संस्थान के ध्यान पर जोर दिया।

भारतीय किसानों ने तापमान परिवर्तन को चावल, मक्का के लिए अनुकूलित किया, लेकिन गेहूं के लिए नहीं: इलिनोइस अध्ययन

यह निर्धारित करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन ने भारत में महत्वपूर्ण अनाज फसलों की पैदावार को कैसे प्रभावित किया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 60 से अधिक वर्षों के डेटा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि भारतीय किसान मक्का और चावल के लिए तापमान भिन्नता को समायोजित कर सकते हैं लेकिन गेहूं के लिए नहीं।

कृषि अर्थशास्त्र जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन का उद्देश्य फसलों पर जलवायु परिवर्तन के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करना था। जहां अधिक वर्षा के कारण चावल का उत्पादन बढ़ा है, वहीं गेहूं और मक्का की पैदावार में कमी आई है। अध्ययन की लेखिका मधु खन्ना ने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि किसान विभिन्न क्षेत्रों और फसलों के लिए अपनी रणनीति को अनुकूलित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, गर्म क्षेत्रों के जिलों ने ठंडी जलवायु वाले जिलों की तुलना में गर्म जलवायु में बेहतर प्रदर्शन किया।

मधु ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निर्धारित करने के लिए हर साल अध्ययन किया जाता है। लेकिन इस शोध से जलवायु संबंधी अंतरों की व्याख्या नहीं की जा सकती है; केवल ऋतुओं में परिवर्तन हो सकता है। मधु उपभोक्ता अर्थशास्त्र और कृषि अर्थशास्त्र पढ़ाने वाली प्रोफेसर हैं।

सुरेंद्र कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि अधिक उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई का बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। सुरेंद्र कुमार के अनुसार ये क्षेत्र मानसून के मौसम पर कम निर्भर हैं। उन्होंने दावा किया कि परिणामस्वरूप, लघु और दीर्घकालिक प्रभावों के बीच अंतर है। जलवायु परिवर्तन फसलों को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में प्रिवेंशन वेब बताता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के खतरे को दूर करने में अपने किसानों की सहायता कर सकता है।

अप्रयुक्त जिलों में दूध, पशु उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र

महामारी के बाद बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन विभाग देश के तथाकथित आकांक्षी जिलों में दूध और मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार समर्थित एजेंसी द्वारा दूध-वसा के आयात से बचने में कामयाब रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 2022-23 में दशकों में पहली बार।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 15 अप्रैल को कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक मक्खन जैसी डेयरी वस्तुओं का आयात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपूर्ति में सुधार हो रहा है, क्योंकि आपूर्ति में कमी के कारण कीमतें एक दशक में सबसे अधिक बढ़ी हैं।

मंत्री ने कहा था कि दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनका मंत्रालय आयात का सहारा लेने के बजाय "अप्रयुक्त क्षेत्रों में टैप करेगा"। सरकार ने 27 राज्यों में 112 जिलों को अधिक सार्वजनिक निवेश के लिए आकांक्षी के रूप में वर्गीकृत किया है क्योंकि वे सामाजिक-आर्थिक मानकों पर अधिकांश अन्य राज्यों से पीछे हैं।

पशुधन जागृति अभियान को लागू करने के लिए, पशुधन क्षमता वाले अप्रयुक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का एक कार्यक्रम, मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 1000 गांवों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

पहले अधिकारी ने कहा, "हम योजनाओं और पशु चिकित्सा सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं और उन्हें आकांक्षी जिलों में कैसे लागू किया जा सकता है।"

पशुधन जनगणना, 2019 के अनुसार, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पशुधन आबादी 536.76 मिलियन है, जो लगभग 80 मिलियन किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत है। कृषि क्षेत्र में देश के सकल मूल्य वर्धित, या जीवीए में पशुधन का 30% हिस्सा है। जीवीए आय का एक उपाय है जो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से शुद्ध कर घटाता है।

स्विच करना आसान: यही कारण है कि भारत के डेयरी किसानों को एथनोवेटरिनरी दवाओं की ओर रुख करना चाहिए

पशुधन रोग उपचार समुदायों के अनुभवों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुए हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, स्थानीय संस्कृति और प्रथाओं में सन्निहित हैं और फिर भी, मानकीकरण और वैज्ञानिक सत्यापन के अभाव में ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया है। अधिक बार नहीं, डेयरी किसान, और कुछ क्षेत्र के पशु चिकित्सक, जानवरों में सामान्य संक्रमणों के इलाज के लिए भी अंधाधुंध एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं।

दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के शोधकर्ताओं ने डेयरी किसानों और पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श के दौरान 2020 और 2021 में एंटीबायोटिक दवाओं के इस तरह के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और अति प्रयोग के प्रमाण पाए।

उन्होंने देखा था कि अधिकांश डेयरी किसान महत्वपूर्ण निकासी अवधि को छोड़ देते हैं- दिनों की एक निर्धारित संख्या जिसके दौरान उपचारित पशु को दूध आपूर्ति श्रृंखला से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक अवशेषों को उसके शरीर से बाहर निकाला जा सके। 2018 में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भी दूध के नमूनों में एंटीबायोटिक अवशेष पाए थे।

डेयरी पशुओं के बीच एक आम संक्रमण जो किसानों को एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भर होने के लिए प्रेरित करता है, वह मास्टिटिस है, जो बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे 100 से अधिक प्रकार के सूक्ष्मजीवों के कारण होता है।

खुरदरे दूध देने, थन के ऊतकों को चोट लगने या अस्वच्छ खेत की स्थिति के कारण होने वाला संक्रमण, स्तन ग्रंथियों में सूजन और दूध नलिकाओं में रुकावट का कारण बनता है। इस प्रकार यह दूध उत्पादन को प्रभावित करता है और दूध के रंग, स्थिरता या यहां तक कि दूध में रक्त की उपस्थिति के परिवर्तन में प्रकट होता है।

ऐसी सामान्य बीमारियों का प्रबंधन करने और दवा के उपयोग को तर्कसंगत बनाने के लिए, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने 2014 में मास्टिटिस कंट्रोल पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम (एमसीपीपी) नामक एक परियोजना शुरू की।

सबर डेयरी में, उन्होंने क्लिनिकल मास्टिटिस से प्रभावित 30 गायों पर एक और परीक्षण किया। एलोवेरा, हल्दी पाउडर और चूने को मिलाकर लाल रंग का लेप बनाया जाता है, जिसे चार से पांच दिनों के लिए दिन में तीन बार मास्टिटिस-संक्रमित क्षेत्र पर लगाया जाता है और मवेशियों को पूरे नींबू खिलाए जाते हैं। दवा ने 29 मवेशियों को ठीक किया, जिसमें एक किसान परीक्षण से बाहर हो गया।

"हमने पाया कि एथनोवेटरिनरी प्रथाएं निवारक और उपचारात्मक दोनों हो सकती हैं। इसका उपयोग किसानों द्वारा स्वयं किसी भी स्थिति के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में किया जा सकता है," एम बालकृष्णन नायर, एमेरिटस प्रोफेसर, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, टीडीयू कहते हैं।

सफल परीक्षण के बाद, सबर डेयरी ने किसानों को इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियनों के अपने नेटवर्क का उपयोग किया। बयाती कहते हैं, 'हमने उन्हें जमीन पर दृष्टिकोण लागू करने के लिए 22 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया।'

2021 में MCPP का खर्च 2,605 लाख रुपये होने का अनुमान था, जिसमें NDDB ने 356 लाख रुपये का भुगतान किया और शेष संबंधित डेयरी सहकारी समितियों द्वारा वहन किया गया। आठ साल बाद, सीएसई के शोधकर्ताओं ने विभिन्न दुग्ध संघों और उत्पादक कंपनियों का दौरा किया। डेयरी किसानों और पशु चिकित्सकों के साथ बातचीत ने एमसीपीपी का उत्साहजनक प्रभाव दिखाया।

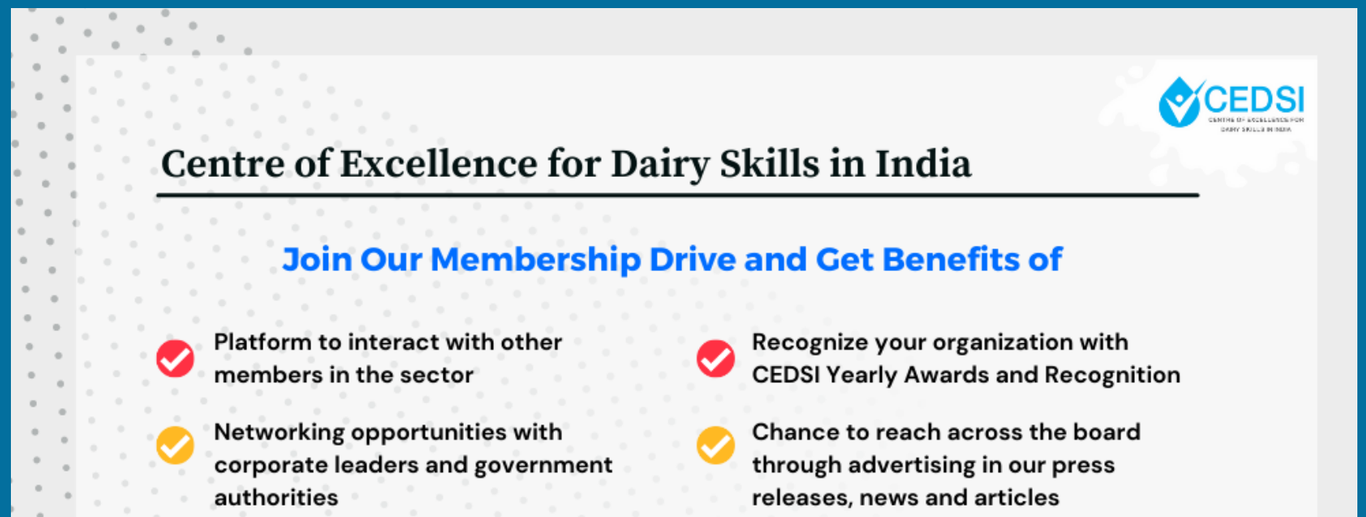

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।